

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

चिकित्सा बोर्ड द्वारा, या चिकित्सा अपील न्यायाधिकरण द्वारा
या कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा।”

(10) खंड 75 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कोई विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत आता है तो निगम और नियोक्ता के बीच किसी भी विवाद का निर्णय ई. एस. आई. न्यायालय को खंड 75 (1) (g) के तहत करना होता है। खंड 75 का उपखंड (3) अधिनियम की खंड 75 (1) में उल्लिखित किसी भी प्रश्न या विवाद पर निर्णय लेने या उससे निपटने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर एक बाधा पैदा करता है। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मेरे सुविचारित विचार में, दीवानी न्यायालय के पास विवाद के मामले में निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और निगम और अभियोक्ता के बीच सभी विवादों का निर्णय ई. एस. आई. न्यायालय द्वारा किया जाना होगा। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है और इसलिए, यह ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। मुझे इस निवेदन में कोई सार नहीं मिलता है क्योंकि विधायिका ने इस अधिनियम को कारखाने या प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लाभ के लिए अधिनियमित किया है, इस

तथ्य के बावजूद कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना है या नहीं। लाभ कमाने के उद्देश्य वाले प्रतिष्ठानों और जहां वर्तमान अधिनियम को लागू करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, के बीच जो अंतर करने की मांग की जाती है, वह अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक और विदेशी है।

(11) पूर्वगामी कारणों से, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है; विचारण न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सिविल न्यायालय के पास वर्तमान वाद का परीक्षण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और मुकदमों को उचित मंच पर अपना उपचार प्राप्त करना चाहिए। कोई लागत नहीं।

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

माननीय ए. एल. बहरी और एन. के. कपूर से पहले, न्यायाधीश

मेसर्स जिंदल स्टील कॉर्पोरेशन,-याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्पाद और कर अधिकारी और अन्य,-प्रतिक्रियादाता।

1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 6577।

20जनवरी, 1994।

भारत का संविधान, 1950-कला।226 और 227-हरियाणा सामान्य
बिक्री कर नियम, 1975-आर. आई. 69 परंतुक उप-नियम (1)-
याचिकाकर्ता पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करके मूल्यांकन किया
गया एकतरफा सर्वश्रेष्ठ निर्णय क्या उचित है-उस सेवा को वैध नहीं
माना गया है-यदि व्यवसाय बंद हो गया था तो निर्धारिती द्वारा बताए
गए पते पर किया जाना आवश्यक है।

माना गया कि सही परिप्रेक्ष्य में, यदि नियम को पढ़ा जाता है, तो यह पता चलेगा कि यदि व्यवसाय बंद कर दिया गया था, तो निर्धारिती द्वारा बताए गए पते पर निर्धारिती की प्रतिस्थापित सेवा की आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक स्थानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वे लागू होते हैं। प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने फरीदाबाद में व्यवसाय बंद करने के बाद मूल्यांकन प्राधिकरण को अपना दिल्ली का पता बताया था। निस्संदेह, जैसा कि विवादित आदेशों में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के दिल्ली पते पर पंजीकृत नोटिस भेजे गए थे, जो निर्धारिती के उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस प्राप्त किए गए थे। हालाँकि, प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने के लिए, याचिकाकर्ता के दिल्ली के पते पर नोटिस नहीं भेजे गए थे। इस तरह की सेवा को केवल फरीदाबाद के पते पर लागू करने की मांग की गई थी, जहां स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता नहीं रह रहा था और उसने व्यवसाय बंद कर दिया था और अधिकारियों को अपने दिल्ली के पते के बारे में सूचित किया था। यदि प्रतिस्थापित सेवा याचिकाकर्ता के दिल्ली पते पर लागू की गई होती, तो शायद हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता। इस प्रकार, रिट याचिका

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

को अनुमति देते समय, हम कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए मामले को निर्धारण प्राधिकरण, फरीदाबाद को भेजते हैं।

(पैरा 3)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमिता गुप्ता,

आर. के. जोशी, प्रतिवादीओं के लिए एडिशनल ए. जी., पंजाब।

ए. एल. बहरी, जे.

1. यह रिट याचिका मेसर्स जिंदल स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा उन विषम परिस्थितियों में दायर की गई है, जहां निगम के साथ प्रथम दृष्टया अन्याय हुआ प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता निगम फरीदाबाद में काम कर रहा था। याचिकाकर्ता के खिलाफ जिन निर्धारण वर्षों के लिए आदेश पारित किए गए हैं, वे 1985-661 और 1986-87 थे। यह फर्म हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता थी। 1986 में फरीदाबाद में याचिकाकर्ता फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया गया था और अधिनियम के तहत अधिकारियों को सूचना भेजी गई थी-पत्र संलग्नक पी-2 के माध्यम से। मूल्यांकन प्राधिकरण ने बाद में एक एकपक्षीय सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर

अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामले को न्यायाधिकरण में ले जाया गया, जिसने भी मूल्यांकन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। संलग्नक पी-6 न्यायाधिकरण द्वारा 27 जनवरी, 1993 को पारित आदेश है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर इस रिट याचिका में इन आदेशों पर आपत्ति जताई गई है।

2. प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, याचिकाकर्ता के दावे को चुनौती देते हुए प्रतिवादी की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है।

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

3. इस मामले में विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद के पते पर याचिकाकर्ता निगम पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करके एकपक्षीय सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन तैयार करने में मूल्यांकन प्राधिकरण को उचित ठहराया गया था?हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 का नियम 69 इस प्रकार है:-

“आर. 69-नोटिस की सेवा -

(1) अधिनियम या इन नियमों के तहत नोटिस निम्नलिखित तरीकों में से एक द्वारा दिए जाएंगे:-

(a) नोटिस की एक प्रति प्राप्तकर्ता को या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अन्य एजेंट को या उस व्यवसाय के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में वह व्यापारी के रूप में पंजीकृत है, या व्यापारी के साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को हाथ से वितरित करके;

(b) पंजीकृत डाक द्वारा:

बशर्ते कि उपरोक्त में से किसी भी तरीके से ऐसी कोई सूचना

देने का प्रयास किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि प्राप्तकर्ता सूचना देने से बच रहा है, या किसी अन्य कारण से जो ऐसे प्राधिकारी की राय में पर्याप्त है कि सूचना उपरोक्त में से किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती है, तो उक्त प्राधिकारी कारणों को दर्ज करने के बाद इसकी एक प्रति चिपकाकर सूचना देने का कारण बनेगा -

- (i) यदि प्राप्तकर्ता व्यापारी है, व्यापारी के कार्यालय के किसी विशिष्ट भाग पर या उस भवन पर जिसमें व्यापारी का कार्यालय स्थित है, या व्यापारी के व्यवसाय के स्थान के किसी विशिष्ट भाग पर विक्रेता द्वारा उक्त प्राधिकारी को अंतिम बार सूचित किया गया है या उस स्थान पर जहां उसे अंतिम बार व्यवसाय करने के लिए जाना जाता है; या
- (ii) यदि प्राप्तकर्ता विक्रेता नहीं है, तो उसके निवास या कार्यालय के किसी विशिष्ट भाग में उस भवन में जिसमें उसका निवास या कार्यालय स्थित है और ऐसी सेवा उतनी ही प्रभावी मानी जाएगी जैसे कि वह प्राप्तकर्ता

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

पर व्यक्तिगत रूप से की गई हो:

बशर्ते कि क्या वह अधिकारी, जिसके कहने पर नोटिस दिया जाना है, पूछताछ पर संतुष्ट है कि उक्त कार्यालय, व्यावसायिक स्थान या निवास का अस्तित्व ज्ञात नहीं है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

अधिकारी लिखित आदेश द्वारा अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक के तहत नोटिस की सेवा की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।”

यह परंतुक के तहत उप-नियम (i) है, जो विचार के लिए प्रासंगिक है। सही संभावना में, यदि नियम पढ़ा जाता है, तो यह पता चलेगा कि यदि व्यवसाय बंद कर दिया गया था, तो निर्धारिती द्वारा बताए गए पते पर निर्धारिती की प्रतिस्थापित सेवा की आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक स्थानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वे लागू होते हैं। प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने फरीदाबाद में व्यवसाय बंद करने के बाद मूल्यांकन प्राधिकरण को अपना दिल्ली का पता बताया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, जैसा कि विवादित आदेशों में उल्लेख किया गया

है, याचिकाकर्ता के दिल्ली के पते पर पंजीकृत नोटिस भेजे गए थे, जो निर्धारित के उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस कर दिए गए थे। हालाँकि, प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने के लिए, याचिकाकर्ता के दिल्ली के पते पर नोटिस नहीं भेजे गए थे। इस तरह की सेवा को केवल फरीदाबाद के पते पर लागू करने की मांग की गई थी, जहां स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता नहीं रह रहा था और उसने व्यवसाय बंद कर दिया था और अधिकारियों को अपने दिल्ली के पते के बारे में सूचित किया था। यदि प्रतिस्थापित सेवा याचिकाकर्ता के दिल्ली पते पर होती, तो शायद हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर मामला लड़ने का एक और अवसर देना उचित समझते हैं, क्योंकि याचिका में आरोप है कि याचिकाकर्ता के पास एसटी-15 ए फॉर्म हैं, जिसके आधार पर वह राहत का दावा कर सकता है; दूसरे शब्दों में, इसे पेश न करने के लिए, मूल्यांकन तैयार किया गया है। इस प्रकार, रिट याचिका को अनुमति देते समय, हम कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए मामले को निर्धारण प्राधिकरण, फरीदाबाद को भेजते हैं। याचिकाकर्ता एसटी-15 पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा। निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष एक प्रपत्र। दलों को अपने वकील द्वारा से 21 फरवरी, 1994 को वहां उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

M/s Jindal Steel Corporation R. Excise and Taxation Officer
and another (A. L. Bahri, J.)

J.S.T

माननीय आर. पी. सेठी और सतपाल, न्यायाधीश

सतीश और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग और अन्य,-प्रतिक्रियादाता

1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 8584

18जनवरी, 1994

भारत का संविधान-अनुच्छेद 284 और 285-लोक सेवा आयोग-
परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य-परिणाम रद्द करना-इस तरह के
रद्द करने की वैधता।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग
के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य
उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक
और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक

I.L.R. Punjab and Haryana 1995(1)

होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

I

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा